सावित्री गोयनका

बनाम

कुसुम लता दमानी और अन्य

02 नवम्बर, 2007

(अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जेजे.)

न्यायिक औचित्य - उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता को तामील बिना सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन को धारा 438 सीआरपीसी के तहत परिवर्तित कर दिया और अंतरिम सुरक्षा प्रदान की - आरोपी के पक्ष में राहत देने के लिए औचित्य - उचित नहीं - आरोप पत्र दाखिल करना या अनुदान देना बिना किसी नतीजे के जमानत - मामले को नए विचार के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया गया - आपराधिक प्रक्रिया संहिता संहिता 1973 प्रतिवादी ने विविध आपराधिक याचिका दायर कि। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को अपीलकर्ता को तामील का निर्देश दिया लेकिन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को अपीलकर्ता को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। इस बीच, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि उसे पहले ही उच्च न्यायालय से राहत मिल चुकी है। इसके बाद, अपीलकर्ता पर तामील किए बिना, उच्च न्यायालय ने आवेदन को धारा 438 के तहत परिवर्तित कर दिया। धारा 482 सीआरपीसी की धारा में जमानत दी गई।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आवेदनों को परिवर्तित करने की प्रथा। धारा 438 या 439 सीआरपीसी के संदर्भ में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी नहीं मिली है. इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता को नोटिस और तामील जारी करने का निर्देश दिया गया था जो प्रतिवादी

क्रमांक 1-अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया है। तथ्य यह है कि आरोप-पत्र दायर किया गया है या जमानत दी गई है, इसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है क्योंकि नियमित जमानत आवेदन में राहत प्रतिवादी नंबर 1 को दी गई अंतरिम सुरक्षा के मद्देनजर दी गई प्रतीत होती है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया जाता है। पक्षों को 2 नवंबर, 2007 को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

अरिजीत पसायत, जे.-

1. अनुमति दी गई

2. हालाँकि अपील के संबंध में कई बिंदुओं पर आग्रह किया गया था, हमने पाया कि उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को एक आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है। हालाँकि इसने अपीलकर्ता को नोटिस जारी किया था, लेकिन अपीलकर्ता को सुने बिना ही मामले का निपटारा कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने जमानत याचिका यानी विविध आपराधिक याचिका दायर की थी। याचिका संख्या 2945/2004 दिनांक 10.12.2004. अदालत ने अपीलकर्ता पर सेवा का निर्देश दिया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता को नोटिस की कोई तामील नहीं हुई थी। अपीलकर्ता के अनुसार, कार्यवाही के बारे में जानने पर, विविध आपराधिक आवेदन संख्या 4653/05 विविध आपराधिक आवेदन संख्या 2945/04 में दाखिल किया गया था. उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन पर 14.7.2005 को नोटिस जारी करने में प्रसन्नता व्यक्त की और उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को अपीलकर्ता को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी, प्रतिवादी नंबर 1 की जमानत अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी कि उसे पहले ही उच्च न्यायालय से राहत

मिल चुकी थी। 22.9.2005 को, अपीलकर्ता पर तामील किए बिना, उच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सी.आर.पी.सी.') की धारा 482 के तहत आवेदन को धारा 438 सीआर.पी.सी. में बदल दिया। और अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि कई तथ्य दबाए गए थे। तथ्यात्मक परिदृश्य के बारे में गलत धारणा देकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय को आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए राजी किया। जवाब में, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि वास्तव में आदेश में कोई खामी नहीं है। किसी भी स्थिति में, आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और प्रतिवादी नंबर 1-अभियुक्त को पहले ही नियमित जमानत दी जा चुकी है। जमानत अर्जी पर पारित आदेश की प्रति रिकार्ड के लिए दाखिल कर दी गई है।

4. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आवेदनों को धारा 438 या 439 सीआरपीसी के संदर्भ में जमानत के लिए परिवर्तित करने की प्रथा इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता को नोटिस और तामील जारी करने का निर्देश दिया गया था जो प्रतिवादी क्रमांक 1-अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया है। तथ्य यह है कि आरोप-पत्र दायर किया गया है या जमानत दी गई है, इसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है क्योंकि नियमित जमानत आवेदन में राहत प्रतिवादी नंबर 1 को दी गई अंतरिम सुरक्षा के मद्देनजर दी गई प्रतीत होती है।

5. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया जाता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। अनावश्यक विलंब से बचने के लिए पक्षों को 23 नवंबर, 2007 को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष बिना

किसी पूर्व सूचना के उपस्थित होने दें। यदि कोई पक्ष उस दिन उपस्थित नहीं होता है, तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि विद्वान एकल न्यायाधीश मामले को कानून के अनुसार निपटाएगा। उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध है कि वे इस मामले को रोस्टर के अनुसार विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दें।

उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हरि वल्लभ खत्री (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।